

**दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कालोनियों को नियमित किया जाना**

2385. श्री दयाराम शाक्य : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाण्डव नगर के 'ई०' 'एफ०' और 'पी०' ब्लॉक, जनता गाँव, 'पी' ब्लॉक पाण्डव नगर, प्रताप नगर, आचार्य निकेतन और शास्त्री नगर को ऐसी कालोनियों की सूची में नहीं रखा गया है जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण का नियमित करने का विचार है जबकि इन कालोनियों के निवासियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को विकास प्रभार की पहली किस्त अदा कर दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन कालोनियों को नियमित करने का है ?

**संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) :**

(क) से (ग) यद्यपि, इन कालोनियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कालोनियों की पहले वाली सूची में शामिल किया गया था परन्तु इनके नाम उस समय हटा दिये गये जब दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा सरकारी नीति के अनुसार अनुमोदित की जाने वाली अनधिकृत कालोनियों की सूची संशोधित की गई। तथापि, दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि यमुनापार क्षेत्र में अनधिकृत कालोनियों की संशोधित सूची की समीक्षा की जा रही है। अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त की गई तकनीकी समिति द्वारा अब

612 अनधिकृत कालोनियों की सूची की जांच का कार्य किया जा रहा है और इस मामले पर उचित कार्यवाही तब की जायेगी जब यह समिति अपनी जांच पूरी कर लेगी।

**निम्न आय वर्ग और मध्य आय वर्ग के आबंटितियों का डी० डी० ए० द्वारा मांग पत्र जारी करना**

2386. श्री दयाराम शाक्य : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लगभग 5000 उन व्यक्तियों को मांगपत्र जारी किये हैं, जिन्हें निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के फ्लैट आबंटित किए गए हैं, जिसमें उनसे सितम्बर तक हजारों रुपये जमा कराने को कहा गया है जब कि आबंटित फ्लैटों का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है और ना ही उनका निर्माण जून-जुलाई, 1983 तक पूरा होने की कोई सम्भावना है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके कारण क्या हैं, जबकि अधिकांश लोग ऋण लेने के बाद धनराशि का भुगतान करेंगे उन्हें मकानों का कब्जा अभी नहीं मिलेगा ?

**संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) :** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**Afforestation of Arawali Hills**

2387. SHRI GHULAM MOHAMMAD KHAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of large scale felling of trees

in the Arawali Hills and denudation of greenery of the areas;

(b) whether a scheme is under preparation to afforest the Arawali Hills;

(c) whether it is also a fact that the SIDA has given assistance for the programme; and

(d) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) No, Sir. However, the government is aware that the Arawali Hills are progressively becoming bereft of vegetation due to excessive biotic factors such as over-grazing and browsing by cattle and over-dependence of the people on the tree cover for meeting their needs of fuelwood, small timber etc.

(b) A scheme is under preparation for re-vegetating the Arawali Hills in Haryana State.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise, in view of (c) above.

#### **Manikhera Mohinisagar Irrigation Scheme**

2388. SHRI SUBHASH YADAV: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have approached the Central Government for taking clearance of Manikhera Mohinisagar Irrigation Scheme in that State; and

(b) if so, whether the scheme has since been cleared by the Central Government and if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI Z. R. ANSARI) : (a) The Hon'ble Member is pre-

sumably referring to the Sindh River Project Phase-II which is a multipurpose project envisaging construction of a dam across Sindh River near village Manikhera to form Mohinisagar reservoir. Project report of this scheme was received in the Central Water Commission from the Government of Madhya Pradesh in 1978 for technical examination and obtaining approval of Planning Commission.

(b) The Project being a major scheme, inter-alia, envisaging hydro-power generation was examined in Central Water Commission and Central Electricity Authority. Part replies to their comments have been received recently on which further clarifications have been sought, while replies of the state to other comments are still awaited.

The clearance of the project will depend upon the State Government in promptly furnishing complete replies to the comments/clarifications sought by the Central Water Commission and Central Electricity Authority and subject to its techno-economic feasibility and cost effectiveness being established.

#### **Effect on Ku-Babul on Wheat Crop**

2389. SHRI SUBHASH YADAV : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have seen the press report appeared in the Indian Express dated 23 September, 1982 wherein it has been stated that ku-babul an exotic variety of plant imported from tropical America as a panacea for our fodder, fuel and timber requirements, may infect the wheat crop with a dangerous fungus, fusarium semitectum ; and

(b) if so, the steps taken by Government in regard thereto ?